दैनिक जागरण

वही कर्म सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा सुख दे

बेनकाब होता पाकिस्तान

आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जिस तरह ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया उससे यही पता चलता है कि आतंकवाद का निर्यात करने वाला यह पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय आतंकियों के ढांचे को बनाए रखे हुए है। एफएटीएफ ने यह पाया कि पाकिस्तान ने उसके निर्देशों पर मामूली रूप से ही पालन किया। इस संस्था ने उसे इसके लिए चेताया भी कि वह आतंकी ढांचे को खत्म करने के प्रति गंभीर नहीं और अगर उसने अपने रवैये को नहीं बदला तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है। निःसंदेह यह पाकिस्तान को शर्मसार करने और उसके असली चेहरे को उजागर करने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि वह आतंकवाद को संरक्षण देने की अपनी नीति का परित्याग करेगा। इसका संकेत एफएटीएफ के इस निष्कर्ष से तो मिला ही कि पाकिस्तान आतंकवाद के नासूर को समझने के लिए तैयार नहीं, इस संस्था की बैठक के एक दिन पहले आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठनों पर पाबंदी की दिखावटी कवायद से भी मिला था। पाकिस्तान ने यह कवायद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही की थी। यह अच्छा हुआ कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हुआ और ग्रे सूची से बाहर आने के उसके इरादों पर पानी फिरा, लेकिन और भी अच्छा होता कि उसे मोहलत देने के बजाय काली सूची में डाला जाता। यदि भारत की तमाम कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो सका तो इसका कारण यही लगता है कि कुछ देशों ने पाकिस्तान की पैरवी की।

भारत को एफएटीएफ की अगली बैठक के लिए और तैयारी करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान को बच निकलने का कोई मौका न मिलने पाए। पाकिस्तान की और तगड़ी घेरेबंदी की जरूरत न केवल एफएटीएफ में है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी। इससे एक सीमा तक ही संतुष्ट हुआ जा सकता है कि पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया और फिर एफएटीएफ ने भी, क्योंकि यह तथ्य सामने आया कि चीन यह चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुलवामा हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में सीमा पार आतंकवाद शब्द का जिक्र न हो। चीन की इस चाहत के चलते यह प्रस्ताव करीब एक हफ्ते रुका रहा। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना का बेशर्मी के साथ बचाव करने वाले चीन के प्रति भारत अपनी रीति-नीति बदले, यह समय की मांग है। चीन के भारत विरोधी रवैये की अनदेखी करते रहने का कोई औचित्य नहीं। अब जब यह साफ हो चुका है कि चीन भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान संरक्षित आतंकी ढांचे का बचाव करने में लगा हुआ है तब भारत को यह देखना ही होगा कि उसे दबाव में कैसे लाया जाए? यह सही समय है जब इस पर गहनता के साथ विचार हो कि हुआवे सरीखी उन चीनी कंपनियों पर नकेल कैसे कसी जाए जिनसे दुनिया के अन्य देश सशंकित हैं।

राहत भरा कदम

झारखंड सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए हर साल जाति प्रमाणपत्र बनाने की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब उनको एक ही बार जाति प्रमाणपत्र बनवाना होगा। एक बार बना प्रमाणपत्र आजीवन चलेगा। निश्चित ही यह राहत देने वाला फैसला है। लंबे समय से इसकी मांग ओबीसी समाज के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई जा रही थी। यह निर्णय बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण यह मामला इतने लंबे वक्त तक अटका। राज्य सरकार ने ओबीसी की जाति प्रमाणपत्र से जुड़ी स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की है। अब उन्हें केवल एक ही बार जाति प्रमाणपत्र बनवाना होगा, लेकिन उन्हें हर साल इस बात का शपथ पत्र दायर करना होगा कि वे क्रीमी लेयर में नहीं हैं। शपथ पत्र गलत होने की स्थिति में उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पहले पिछड़ी जातियों के लिए क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू होने की वजह से उन्हें हर साल जाति प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता था। उसी में उनकी आमदनी का भी उल्लेख होता था। वहीं छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अब एक ही बार जाति प्रमाणपत्र बनवाना होगा। इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। राज्य में ओबीसी के लिए लागू छात्रवृत्ति योजना में क्रीमी लेयर का प्रावधान न होने की वजह से यह नियम बनाया गया है। भूमिहीन का जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ग्रामसभा के माध्यम से जांच कराई जाएगी। इसमें आवेदक के पूर्वजों की जानकारी शामिल होगी। ग्रामसभा की रिपोर्ट के आधार पर भूमिहीन को जाति प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा। राज्य सरकार ने जाति प्रमाणपत्र से जुड़ी अन्य तकनीकी दिक्कतों का भी समाधान किया है। तय किया है कि जाति प्रमाणपत्र सिर्फ अंचलाधिकारी ही बनाएंगे। यह भी एक अहम फैसला है। दरअसल कई राज्यों में उपायुक्त एवं एसडीओ के स्तर से जारी प्रमाणपत्रों की मांग की जाती थी। इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। ओबीसी की जाति प्रमाणपत्र से जुड़ी स्पष्ट गाइडलाइन में तमाम समस्याओं का समाधान किया गया है। यह नीति सिर्फ झारखंड ही नहीं, राज्य के बाहर जाने वालों लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी।

हमारी गलतियों से बिगड़े कश्मीर के हालात

प्रकाश सिंह

पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक ही उपाय है, जो खेल पाकिस्तान कश्मीर में खेल रहा है वही खेल हम उसके सिंध एवं बलूचिस्तान में खेलें

कश्मीर के पुलवामा की भयंकर आतंकी घटना आजकल देश-विदेश में चर्चा का विषय है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। घटना क्यों हुई और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहां कमजोरी रही? इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। सच तो यह है कि कश्मीर में हम 1948 से ही गलतियां करते चले आ रहे हैं। गलतियों का घड़ा जब भरने लगता है तो उसका खामियाजा हमें इसी प्रकार की जघन्य घटनाओं के रूप में देखना पड़ता है। संक्षेप में देखें तो नेहरू जी का कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना ही एक गलत कदम था, क्योंकि उस समय भारतीय फौज पाकिस्तानी और कबायली आक्रमणकारियों को खदेड़ रही थी और यदि उसे कुछ समय और मिल जाता तो संपूर्ण कश्मीर भारत के अधिपत्य में होता। बाद में नेहरू जी का यह कहना भी अनावश्यक था कि कश्मीर के भविष्य का अंतिम निर्णय वहां के लोगों की इच्छा जान लेने के बाद होगा। 1965 में पाकिस्तान को हराने के बाद भी भारत ने जीते हुए, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ भू-भाग, पाकिस्तान को लौटा दिए, जैसे हाजी पीर की पहाड़ी। 1971 में पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने शिमला में ऐसी गलती की जो उनके स्वभाव से एकदम विपरीत थी। पाकिस्तान के 90 हजार फौजी हमारे कैद में थे और जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से दया की भीख मांग रहे थे। यदि इंदिरा गांधी ने दृढ़ता दिखाई होती तो कश्मीर की समस्या का शिमला में ही स्थाई समाधान हो जाता। 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रुबैया सईद को छुड़ाने के लिए आतंकियों को रिहा किया। आतंकियों को लगा कि एक अपहरण से उन्होंने भारत सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 1999 में भी एक शर्मनाक घटना तब हुई जब भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को छुड़ाने के लिए तीन आतंकियों को कांधार ले जाकर रिहा कर दिया। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी था। इससे स्पष्ट होता है कि आतंकवाद से निपटने में कमजोरी का कालांतर में कितना भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की सरकार के दौरान सुरक्षा बलों पर जो अंकुश लगाया गया, उससे उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ा। सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो देखे गए जहां लड़के सुरक्षा बलों को दौड़ा रहे थे। सुरक्षा बलों को संयम बरतने के आदेश थे। इन घटनाओं से पत्थरबाजी करने वालों का दुस्साहस बढ़ता गया। कश्मीर के बिगड़े हालात हमारी नीतियों के बराबर ढलान पर होने का चरमोत्कर्ष हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार को अब करना क्या चाहिए? अभी तक सरकार ने दो कदम उठाए हैं। पहला यह कि पाकिस्तान को दिया हुआ सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया। यद्यपि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका पाकिस्तान पर कोई खास असर नहीं पहुंचेगा। दूसरा यह कि अलगाववादी नेताओं को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले ली गई। उनको सुरक्षा देना आस्तीन के सांप को दूध पिलाना जैसा था, परंतु सरकारें बड़े प्रेम से ऐसा करती रहीं। ये दोनों कदम सही होते हुए भी अपर्याप्त हैं। भारत सरकार को निम्नलिखित दस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत काम करना चाहिए।

अवधेश राजपूत

पहला, कश्मीर समस्या वास्तव में घाटी तक ही सीमित है। लद्दाख एवं जम्मू क्षेत्र आतंकवाद या अलगाववाद से प्रभावित नहीं हैं। उचित होगा यदि कश्मीर को तीन प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाए। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश भी घोषित किया जा सकता है। ऐसा करने के बाद कश्मीर घाटी में देश विरोधी तत्वों से एक सीमित क्षेत्र में निपटना आसान हो जाएगा।

दूसरा, आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को हमें और सुदृढ़ बनाना होगा, विशेष तौर से आतंक प्रभावित क्षेत्रों में। सुरक्षा बलों को जिन संसाधनों की आवश्यकता हो वे उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। उनके बीच अच्छा समन्वय और अभिसूचना का पर्याप्त आदान-प्रदान भी हो।

तीसरा, हमारी लड़ाई अलगाववाद और आतंकवाद से है, आम कश्मीरी से नहीं। यह हमें सदैव याद रखना होगा। कश्मीरी युवा, जो इस्लामिक स्टेट के दर्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं या लश्कर या जैश के सिपाही बनने को तैयार हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका सही विश्लेषण कर उनका निदान करना होगा।

चौथा, पाकिस्तान कैसे आतंकियों को धनराशि एवं अन्य संसाधनों द्वारा मदद करता है, इसकी समुचित जानकारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ को दी जाए ताकि वह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर सके।

पांचवां, प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष सुधार हो। लोगों में असंतोष सामान्यतः प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण होता है, विशेष तौर से जब सरकारी तंत्र भ्रष्ट या संवेदनहीन हो जाता है।

छठा, संविधान की धारा-370 के बारे में भी बहुत दिन से मंथन हो रहा है। अब शायद समय आ गया है कि इस धारा को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे केवल अलगाववाद को ही बल मिल रहा है। कश्मीरियों को उनका हक अवश्य मिलना चाहिए, परंतु उनकी बेजा मांगों पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सातवां, सिंधु नदी समझौते पर भी पुनर्विचार हो। नेहरू जी की उदारता के कारण हम पाकिस्तान को उसके हक से अधिक पानी दे रहे हैं। समझौते पर पुनर्विचार करने में समय लग सकता है, क्योंकि यह विश्व बैंक के तत्वावधान में हुआ था, परंतु क्या दंडात्मक कार्रवाई के रूप में हम एक महीने तक पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद नहीं कर सकते? यह पाकिस्तान की हिंसा का एक अहिंसक जबाव होगा।

आठवां, आतंकवाद और अलगाववाद से हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। दुर्भाग्य से आतंकवाद से लड़ने वाले कानून को पिछली सरकारें बराबर कमजोर करती गई हैं। पहले 'टाडा' था, बाद में उससे कमजोर 'पोटा' आया और वर्तमान में और लचर 'अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट' यानी यूएपीए है। इस एक्ट को और धार देना उचित होगा।

नौवां, पाकिस्तान से संबंध सुधार के लिए हमने सब कुछ किया, परंतु जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि 'इथोपियन अपनी चमड़ी का रंग नहीं बदल सकता और न ही तेंदुआ अपने शरीर के दाग'। पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। इसका एक ही उपाय है, जो खेल पाकिस्तान कश्मीर में खेल रहा है वही खेल हम उसके सिंध एवं बलूचिस्तान में खेलें। पाकिस्तान को जब तक यह नहीं लगेगा कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है तब तक वह नहीं सुधरेगा।

दसवां, चीन के प्रति भी हमें अपने रुख को नए ढंग से परिभाषित करना होगा। किसी 'बुली' से निपटने का केवल एक ही तरीका है कि उसके आगे झुका न जाए। चीन अगर मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदलता तो उसकी टेलीकॉम कंपनियों को अगर बाहर न किया जाए तो कम से कम इतना दबाव तो डाला जाए कि चीन को पसीना आ जाए।

युद्ध वर्तमान परिस्थितियों का विकल्प नहीं है। बिना तलवार निकाले भी पाकिस्तान के होश ठिकाने लाए जा सकते हैं और चीन को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है।

(लेखक सीमा सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

बाकी है प्रियंका की असली परीक्षा

क्षमा शर्मा

आज का वोटर इतना भोला नहीं कि मात्र परिवार की विरासत और अच्छे व्यक्तित्व के कारण किसी को वोट दे देगा

जब से प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में आने की घोषणा हुई तबसे यही चर्चा हो रही है कि आखिर उनके राजनीति में आने से 2019 के आम चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या वह अपने करिश्मे के कारण कांग्रेस में नई जान फूंकने में कामयाब होंगी? क्या अपनी पार्टी को बहुमत दिला सकेंगी? ऐसे सवाल सुनकर ऐसा लगता है कि अरे अगर इकलौती प्रियंका इतना कुछ कर सकती हैं तो कांग्रेस ने अब तक उन्हें राजनीति से दूर क्यों रखा? राहुल गांधी ने इस बारे में कहा था कि वह अब तक सक्रिय राजनीति में इसलिए नहीं आईं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे। हालांकि प्रियंका राजनीति में हमेशा सक्रिय रही हैं। वह राहुल और सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्रों में जाकर प्रचार भी करती रही हैं। वहां उन्हें हर बार कोई भारी सफलता मिली हो, ऐसा भी नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनके बाल इंदिरा गांधी जैसे हैं। वह बहुत सौम्य हैं और बोलती भी अच्छा हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, क्या वह मात्र इससे प्रभावित हो सकती है कि प्रियंका इंदिरा जैसी दिखती हैं? आज वक्त बदल गया है। सूचना तकनीक के कारण छोटी-छोटी खबरें सिर्फ शहरी लोगों तक ही नहीं, गांव के लोगों के भी पास हैं। आज लोगों का पहले की तरह कोई गुरु भी नहीं रहा जिससे वे राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके वोट देने का मन बनाते हों। ऐसे में चुनाव के बाद ही प्रियंका की भूमिका का सही-सही आकलन हो सकेगा।

अतीत में जब भी चुनाव आए हैं कांग्रेस के अंदर से मांग उठती रही है कि प्रियंका लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस बचाओ। अब जब वह सक्रिय हो गई हैं तो बहुत से कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं। जगह-जगह उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी की ही तरह उन्हें देवी का अवतार बताया जा रहा है। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की राहुल गांधी की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, लेकिन उनके पास देश की समस्याओं से निपटने का कौन-सा नक्शा है? उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? इस पर शायद ही कोई बात की गई। क्या मात्र गांधी परिवार की होने के नाते वह चुनाव में कामयाब हो जाएंगी? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी भी तो गांधी परिवार से हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। फिर अभी तक उन्हें वैसी सफलता क्यों नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी? क्या प्रियंका इसलिए सफल होंगी कि वह एक महिला हैं, एक मां हैं, एक पत्नी हैं? उनके पति राबर्ट वाड्रा ने एक भावुक-सी पोस्ट भी लिखी कि प्रियंका उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, बच्चों की बेहतरीन मां हैं। जब वह लखनऊ गई थीं तो राबर्ट ने यह भी लिखा था कि उन्होंने प्रियंका को देश को समर्पित कर दिया है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। कई लोगों का यह भी कहना है कि प्रियंका जिस तरह मीडिया में छाई हुई हैं, उन्हें जितना महत्व मिल रहा है, उसके कारण राहुल गांधी ही असुरक्षित हो सकते हैं और प्रियंका को महत्व देना कम कर सकते हैं। लखनऊ के रोड शो के दौरान लोग इस पर भी बहस कर रहे थे कि ट्रक में कौन कहां खड़ा था? राहुल बीच में खड़े थे, प्रियंका किनारे और इससे पता चलता है कि कांग्रेस में मुख्य भूमिका में राहुल ही रहने वाले हैं। प्रियंका तो बस उनकी मददगार होंगी। अगर प्रियंका को लोग सिर्फ इसलिए पसंद करेंगे कि वह इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं तो याद रखा जाना चाहिए कि सिखों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें इसलिए नापसंद भी करेगा। इंदिरा को वे आज तक पसंद नहीं करते। प्रियंका सिखों को कैसे मनाएंगी? क्या वह भी स्वर्ण मंदिर जाकर माफी मांगेगी?

किसी एक व्यक्ति के आने से चुनाव में भारी सफलता मिल सकती है, इस बात पर भरोसा नहीं होता। आखिर प्रियंका गांधी के पास भी ऐसी कौन-सी जादुई छड़ी है कि वह किसी परी की तरह पल भर में लोगों की हर समस्या को दूर कर देंगी। किसानों से लेकर बेरोजगारी, महिलाओं के तमाम मुद्दे, पर्यावरण के मसले, घरेलू मोर्चे पर पैर फैलाता आतंकवाद, सीमाओं की सुरक्षा आदि के मुद्दों से वह कैसे निपटेंगी? उनके पास इन समस्याओं को हल करने का क्या रोड मैप है, किसे पता है? वैसे भी राजनीति में जितनी जल्दी किसी का जादू चढ़ता है, उसे उतरने में भी देर नहीं लगती। जिस नेता से जितनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं उससे निराशा भी उतनी ही जल्दी पैदा हो जाती है। एक तरीके से यह अच्छा भी है, क्योंकि वोटर को इतना भोला नहीं माना जाना चाहिए कि वह किसी को व्यावहारिक तुला पर तौले बिना, मात्र परिवार की विरासत और अच्छे व्यक्तित्व के कारण वोट दे देगा। प्रियंका को आज नहीं तो कल तमाम मुद्दों से दो-चार होना ही पड़ेगा। यही उनकी असली परीक्षा भी होगी। मात्र इंदिरा गांधी जैसी दिखने से वह इस चुनावी परीक्षा में सफल होंगी, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | स्कूटर/स्कूटी की बिक्री

स्रोत: सियाम

कंपनी	जनवरी 2018	जनवरी 2019
महिंद्रा	480	92
पियाजियो	5,480	4,655
यामाहा	29,941	21,599
हीरो	76,062	53,511
सुजुकी	38,274	61,348
टीवीएस	84,140	83,794
होंडा	3,19,318	2,72,170

ऊर्जा

असीम संभावना

आदि काल से आज तक की मानव सभ्यता की यात्रा चकित कर देने वाली है। इस बात का आकलन करने के लिए स्वयं को उस पल में ले जाएं, जब वस्त्रहीन मनुष्य जंगल में रहता था और कंद मूल खाकर क्षुधा तृप्त करता था। जो इसके पास आज है उस समय कल्पना से भी परे रहा होगा। मनुष्य ने सोचा भी नहीं होगा कि वह इतना क्षमतावान है और अपने जीवन को ऐसा रूप दे सकता है। वह चलता गया और रुका नहीं इसलिए यहां तक आ पहुंचा है। निश्चित तौर पर यह उसकी अनंत क्षमताओं की ओर इंगित करता है। भविष्य में वह कहां होगा इसके बारे में भी आज कुछ कहा नहीं जा सकता।

मानव जीवन की संभावनाओं की थाह नहीं पाई जा सकती। इसीलिए जब कोई मनुष्य जीवन में लक्ष्य तय करता है तो एक विरोधाभास दिखाई देता है। लक्ष्य तय करना मनुष्य की अनंत सामर्थ्य को सीमाओं में बांध देने जैसा है। इसी तरह कोई स्वप्न पालना भी बंधन जैसा ही है। जबकि लक्ष्य और स्वप्न पर आज सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। सीमा और बंधन वास्तव में मानव की प्रकृति के ही अंग नहीं हैं। जिन पांच तत्वों से मिल कर मानव तन बना है, उनमें एक आकाश भी है जो अनंत है। मनुष्य को जीवन में ऊपर उठना है तो आकाश बनना होगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है वह चाहे तो जीवन भर ज्ञान अर्जन करे। सेवा, दया, परोपकार, प्रेम जैसे सद्गुणों का कोई अंत नहीं है। वह जितना चाहे इनमें गहरा उतरता जाए।

परमात्मा की भक्ति में जीवन का हर पल उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाने वाला है। गणना करना कि कितनी राह तय कर ली है अथवा आगे तय करनी है, सदैव चिंता एवं भ्रम उत्पन्न करता है। जब एक ही भावना हो कि आगे बढ़ना है तो ऊर्जा बनी रहती है और संकल्प दृढ़ होता है। संसार में सीखने, देखने और करने को बहुत कुछ है। सृष्टि इतनी विशाल है कि एक नहीं कई जीवन कम पड़ जाएंगे। जीवन का हर आगे बढ़ा कदम अगले कदम की संभावना खोलता है। जैसे-जैसे मनुष्य सद्मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, नई-नई संभावनाओं के द्वार खुलते जाते हैं। वह परम तत्व की अनुभूति करता है। परमात्मा के पास मनुष्य को देने के लिए बहुत कुछ है। यह मनुष्य की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी झोली कितनी बड़ी कर सकता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

वायु प्रदूषण का दंश

डॉ. मोनिका शर्मा

हाल के वर्षों में बढ़ते औद्योगीकरण, कचरा जलाने और वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है

वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने के लिए साफ हवा महानगरों में ही नहीं, दूरदराज के कस्बों में भी नहीं बची है। वातावरण की ऐसी स्थितियां वाकई एक खतरा बन गई हैं। इतना बड़ा खतरा कि आज दुनियाभर में 10 फीसद बच्चे समय पूर्व जन्म ले रहे हैं। जर्मनी की एक संस्था द पीफ्रोहेम ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक दमघोंटू हवा से दुनिया भर में समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। इस मामले में भारत की स्थिति बेहद चिंतनीय है। भारत में 15 फीसद बच्चे प्री-मेच्योर पैदा हो रहे हैं। इसके कारण मेंटल डिसऑर्डर, दुबले-पतले, दिव्यांग या आंखों की समस्याओं के साथ बच्चे जन्म ले रहे हैं।

दरअसल भ्रूण तक ऑक्सीजन का प्रवाह मां से ही होता है। ऐसे में अगर मां ही प्रदूषित हवा में सांस ले रही है तो अजन्मे बच्चों में भी दूषित हवा के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है। ऐसे में हवा में मौजूद हानिकारक तत्व न केवल उन्हें, बल्कि कोख में पल रहे बच्चे को भी व्याधियों का शिकार बनाते हैं। इससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह वाकई दुखद है कि हवा में घुले जहर के चलते नई पीढ़ी कई व्याधियों के साथ दुनिया में आ रही है। अध्ययन बताते हैं कि बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामलों की सबसे बड़ी वजह भी हवा में मौजूद हानिकारक तत्व ही हैं।

इस मामले में बीते साल आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'वायु प्रदूषण एवं बाल स्वास्थ्य-साफ हवा का नुस्खा' भी चेताने वाली थी। अध्ययन में कहा गया था कि वर्ष 2016 में भारत समेत निम्न एवं मध्यम आय-वर्ग के देशों में पांच साल से कम उम्र के 98 फीसद बच्चे वायु प्रदूषण के शिकार हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2016 में 1,10,000 बच्चों की मौत की वजह लगातार प्रदूषित होती जा रही हवा रही। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भी भारत के आंकड़े सबसे ज्यादा थे। यह चिंतनीय है कि हमारे यहां साल-दर-साल प्रदूषण की स्थितियां और गंभीर होती जा रही हैं। एशिया के कई देशों में प्रदूषण रोकने की दिशा में काम करने वाली एयर एशिया नामक संस्था के मुताबिक दिल्ली में एक नवजात शिशु भी रोजाना अप्रत्यक्ष तौर पर 15 सिगरेट के बराबर धुआं ग्रहण करता है। कोई हैरानी नहीं कि भारत में दुनिया के किसी भी स्थान की तुलना में श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण भी सबसे अधिक लोगों की मौत होती है।

हाल के वर्षों में बढ़ते औद्योगीकरण, कचरा जलाने और वाहनों की संख्या बढ़ने से भारत में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो हर साल स्थितियां आपातकालीन हो जाती हैं। जाहिर है कि हमारे परिवेश में फैली विषाक्त वायु को लेकर अब चिंता नहीं की गई तो शायद बहुत देर हो जाए। देश के मानव संसाधन और पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचा रही यह समस्या बच्चों के जीवन को भी लील रही है। यह दुखद और चिंतनीय है कि वायु प्रदूषण बड़े होते बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में तो रुकावट डाल ही रहा है, साथ ही साथ जन्म से ही उन्हें गंभीर बीमारियों का शिकार भी बना रहा है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भारत को जोश में होश नहीं खोना है

डॉ. एके वर्मा के आलेख 'पाकिस्तान से निपटने के तौर-तरीके' से यही ध्वनित हो रहा है कि पुलवामा हमले के बाद देश जिस आक्रोशमय पीड़ा से गुजर रहा है, उससे प्रत्येक भारतीय मन अब प्रतिकार के लिए तड़प रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों में भारत को ठंडे दिमाग से प्रतिकार की ऐसी रणनीति बनानी होगी जो दुश्मन के लिए अधिक से अधिक घातक साबित हो। भारत को इस स्थिति में जोश में नहीं, पूरे होशोहवाश में पाकिस्तानी सुरक्षा कवच से घिरे आतंकवादियों से बदला लेने की योजना बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब दुश्मन सतर्क होता है तो जल्दबाजी में बनाई गई रणनीति नुकसानदेह साबित होती है। भारत को इस समय कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अधिक ले अधिक परेशान करने की जरूरत है। यद्यपि भारत ऐसा कर भी रहा है। व्यापारिक स्तर पर पाकिस्तान से असहयोग करते हुए अब भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले तीन नदियों के अपने हिस्से के पानी को रोक दिया है। ऐसे ही भारत से पाकिस्तान को मिलने वाली अन्य रियायतों पर भी पाबंदी लगाने की जरूरत है। हालांकि यह एक लंबी योजना का हिस्सा है और पुलवामा आतंकी हमले से आहत भारतीय जन-मानस अब इतना सब्र नहीं कर पाएगा। अतः अपनी कूटनीति के साथ-साथ पाकिस्तान पर फौरी सैनिक कार्रवाई करना भारत के लिए अपरिहार्य हो गया है। लेकिन इसमें भी ज्यादा जल्दबाजी स्वयं भारत के लिए घातक हो सकती है। इस दृष्टि से भारत को पिछली सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जीरो नुकसान में दुश्मन का शत प्रतिशत सफाया करने की ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

हमारा फर्ज

शहीद जवानों के परिजनों की हरसंभव मदद करना, हर नागरिक, संगठन, समाज, राज्य और राष्ट्र का कर्तव्य है। राष्ट्रहित में प्राणोत्सर्ग करने वाले सैनिक का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, किंतु ये हमारा नैतिक दायित्व और फर्ज है कि शहीदों पर आश्रित उनके परिजनों का भविष्य सुरक्षित और परेशानियों से मुक्त करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही किसी भी स्तर पर न बरती जाए और न ही बर्दाश्त की जाए। देश की सीमा पर जांबाज अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें भी देश के भीतर उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जरा सोचिए कि देश ने केवल अपना एक वीर जवान खोया है, परिजनों ने पिता, बेटा एवं पति को खोया है। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि पूरा देश उनके साथ है।

sonimohit895@gmail.com

एकता जरूरी

पुलवामा हमले के बाद कुछ राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप लगा कर आपस में उलझ रहे हैं। संकट के समय ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक-दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। कश्मीर के लोग हों या कन्याकुमारी के, सब भारत के नागरिक हैं। देश के किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो यह हर किसी को महसूस करना चाहिए। हमारी एकता ही दुश्मन को परास्त कर सकती है, इसलिए एकता को बनाए रखना सबसे जरूरी है।

मोहम्मद आसिफ, दिल्ली

सेना का एक ही धर्म है–राष्ट्रभक्ति

कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यह सेना पर भी लागू होता है। सेना की भी कोई जाति नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है और वह है राष्ट्रभक्ति। प्रत्येक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा अंतिम सांस तक करता है। राष्ट्रभक्ति के अलावा उसके मन-मष्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई अन्य विचार नहीं आता, लेकिन देश के अंदर कुछ विभाजनकारी शक्तियां ऐसी हैं जिनको इन सपूतों में भी जाति-धर्म दिखाई देता है, जो ठीक नहीं है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इतना ही काफी नहीं

सऊदी अरब अब भारत के करीब आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए यह नाकाफी है। जब तक दुनिया के मुस्लिम देश आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान से हर तरह के संबंध नहीं तोड़ लेते तब तक इस समस्या से निपटना आसान नहीं है।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।